Online at: https://researchtrendsjournal.com ISSN No: 2584-282X

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 2; Issue 2; 2024; Page No. 269-272

Received: 06-01-2024
Accepted: 15-02-2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: उच्च शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में

[1]Anurag Kaushik and [2]Dr. Maheep Mishra

[1]Research Scholar, Department of Education, Monad University, Hapur, Uttar Pradesh, India
[2]Professor, Department of Education, Monad University, Hapur, Uttar Pradesh, India

Corresponding Author: Anurag Kaushik

सारांश
व्यक्तिगत शक्तिओं का विकास करना शिक्षा के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्तित्व का विकास समाज के अनुसार होना चाहिए। इसमें हमें समाजिक मूल्यों एवं सिद्धांत को अपने शिक्षा में स्थान अनिवार्य रूप से देना चाहिए। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री लेना कतई नहीं है। यह तो जीवन को समझने वाला एक ऐसा साधन है, जिसके बिना हम एक पल के लिए भी जी नहीं सकते। यह मनुष्य के चरित्र को पवित्र व सुंदर बनाता है। शिक्षा नीति जितनी सशक्त और दूरदृष्टियुक्त होगी वह देश उतना विकास करेगा। भारत में सन् 1968 और 1986 के बाद वर्ष 2020 में तीसरी बार नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। वर्तमान में आयी नई शिक्षा नीति–2020 पिछली दो नीतियों की तुलना में अत्यंत महत्वाकांक्षी व दूरगामी परिणामों का सफलता संकल्प है। भारत सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के कारण दुनिया भर में फैली सभी नकारात्मकताओं के बीच एक स्वागत योग्य बदलाव और ताज़ा खबर थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कई लोगों के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, वे कुछ ऐसे थे जिनकी कई शिक्षाविदों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालाँकि शिक्षा नीति ने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समान रूप से प्रभावित किया है, यह लेख मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं।

मुख्य शब्दः सामाजिक प्राणी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समाज, विकास

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने मे सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार मे निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैष्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति मे ं यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को, छात्रों मे मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैं और वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवत्ति के हों। यह एक व्यक्ति को रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना और 21 वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। नई

शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है, और इसमे मुख्य आकर्षण बहु–विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जिसमे प्रत्येक जिले मे या उसके पास कम से कम एक छात्र पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, बेहतर छात्र अनुभव के लिए मूल्यांकन और समर्थन, एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों मे उत्कृष्ट सहकर्मी–समीक्षा कार्य और प्रभावी ढंग से बीज अध्ययन का समर्थन करेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 पांच स्तंभों पर केंद्रित हैः वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही – निरंतर सीखने की प्रकिर्या को सुनिश्चित करने के लिए। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण 18 उत्पादक रोजगार और अच्छे काम की ओर अग्रसर होना, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है और 2040 तक भारत मे प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को बदलने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है जिससे वो नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सके। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति बहु–विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित संचार, समस्या–समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

2. समस्या का विवरण

शिक्षा किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का अनिवार्य अंग है! यह मानव मस्तिष्क तथा चरित्र का परिष्कार करती है ! शिक्षा के द्वारा न केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी होता है द्य भारतीय शिक्षा में राष्ट्र विचारधारा का सीधा संबंध भारतीय राष्ट्रीयता से रहा है द्य सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के लोगों ने समझा कि भारतीय शिक्षा में भारतीयता और राष्ट्रीयता स्वाभाविक रूप से महत्व का स्थान ग्रहण करेगी किंतु ऐसा नहीं हुआ हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित रही है भारतीय भावनाओ, मूल्यों, मानको को कोई स्थान नहीं मिला द्य परंतु अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय परंपरा, भारतीय मूल्य और राष्ट्रीयता का अवलंब लिया गया है द्य इसे देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में क्रियान्वित करने का प्रयास जारी है द्य जिसके माध्यम से हमारी आने वाली पीढी देश की अस्मिता, उसकी पहचान, तथा परम्परागत मूल्यों एवं परंपराओं से अवगत होंगी द्य हमारी नई शिक्षा नीति भारत एवं भारतीय ता की भावना से घनीभूत है इसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों मां को और प्राचीन ज्ञान तथा कौशल को विशेष स्थान दिया गया है युवाओं में नैतिक मूल्यों का तेजी से हो रहे चरण को भी रोकने के उपायों के रूप में नैतिक शिक्षा को महत्व दिया गया है

प्रस्तुत शोध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नैतिक स्वरूप को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है द्य साथ ही साथ सौहार्द, समन्यव, सास्कृतिक और नैतिक मूल्यो को सामाजिक जीवन में अंगीभूत करने जैसे प्रश्नों को भी विवेचित करने का प्रयास किया गया है द्य शोध का विषय समसमायिक है क्योकि यह वर्तमान समस्या से जुड़ा है द्य चुनौतीपूर्ण भी है क्योकि यह २१ वी सदी की समस्त शैक्षिक समस्या के समाधान का प्रयास करता हैद्य इस समसामयिक चुनौतीपूर्ण विषय को दुरुहता से बचते हुए विवेचित करने का प्रयास किया गया है।

3. अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को देखना।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शाने लिए।

4. अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन पाठ्य, आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें एमएलए हैंडबुक ऑफ रिसर्च के 8वें संस्करण का सख्ती से पालन किया गया है।

- **डेटा संग्रहः** शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण किया गया है।
- **प्राथमिक स्रोतः** प्राथमिक संसाधन नई शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।
- **माध्यमिक स्रोतः** एक माध्यमिक संसाधन एक स्रोत है जो नई शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भ पुस्तकों सहित पुरानी या गैर–मूल जानकारी प्रदान करता है। माध्यमिक स्रोतों में जीवनी, लेखक के कार्यों के महत्वपूर्ण अध्ययन, शोध पत्र और शोध प्रबंध, शोध पुस्तकें, व्यक्तिगत साक्षात्कार, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और अन्य वेबसाइटें शामिल हैं।

5. विवेचना

5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: उच्च शिक्षा में सुधार

यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तनकाल के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नई शिक्षा नीति को स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली मे औपचारिक परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, अब से शैक्षिक सामग्री प्रमुख अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के कोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह तथ्य कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति है, सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने देश में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का अनुभव करने मे मदद मिलेगी। बहु–विषयक संस्थान शुरू करने की नीति कला, मानविकी जैसे सभी क्षेत्रों में नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को सीखने और समग्र रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी।

5.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एनईपी 2020 की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी

के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इसके अलावा, देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) की स्थापना की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआई) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और समान स्तर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, जैसे कि इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, चिकित्सा की आयुष प्रणाली, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उससे आगे के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अवसर वैष्विक गुणवत्ता मानकों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आवासीय सुविधाओं और परिसर में समर्थन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।

5.3 उच्च शिक्षा मे प्रत्यायन

उच्च शिक्षा के नियामक तंत्र मे अन्य प्रमुख कार्यों के बीच एक स्वतंत्र निकाय द्वारा संचालित ''मान्यता'' होगी। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, बशर्ते वे ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हों, अपनी पेशकशों को बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने, जीईआर बढ़ाने और आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए। लर्निंग सर्विस प्रोवाइडर की विश्वसनीयता में सुधार के लिए प्रत्यायन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) के तहत विकसित किया गया है। प्रत्यायन गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है जैसे प्रशिक्षकध्संकाय, आधारभूत संरचनाय कार्यक्रम डिजाइन (विकास और वितरण)य प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (3 आयामः हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर स्किनवेयर) आदि।

5.4 साइबर सुरक्षा मे शिक्षा और कौशल

विश्व आर्थिक मंच 2021 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 'साइबर सुरक्षा विफलता' दुनिया के लिए चैथा सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। जैसा कि चल रही महामारी के कारण शिक्षा और अध्यन पहले ही साइबर स्पेस में चली गई है, प्रत्येक व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार, चूंकि डिजिटलीकरण को अपनाना केंद्र स्तर पर है, इसलिए हमारे नेटवर्क और साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान परिदृश्य में, यह प्रासंगिक हो जाता है कि 'साइबर सुरक्षा लचीलापन' के लिए क्षमता निर्माण को प्रमुख महत्व दिया जाता है और सीखने की धारा के बावजूद उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है।

5.5 उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक सरकारी और निजी क्षेत्रों से उच्च अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट को बढ़ावा मिलेगा। इसे सुगम बनाने के लिए उद्योग आधारित कौशलध्अपस्किलिंगध्रीस्किलिंग के लिए एक मजबूत उद्योग प्रतिबद्धता और शिक्षा जगत के साथ घनिष्ठ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा, ''बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)'' के बारे में ज्ञान बढ़ाने और इससे लाभ प्रदान करने के लिए इसके संरक्षण के लिए कौशल को विकसित करना प्रासंगिक हो जाता है।

5.6 राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ)

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित एनईटीएफ सही दिशा में एक कदम है। शिक्षण–शिक्षण वितरण के सभी आयामों में गुणवत्ता वाले एड–टेक उपकरण शैक्षणिक संस्थानों को जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करने, फायरवॉल को अपनाने और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम (आईडीएस) के अलावा 'गोपनीयता और सुरक्षा' सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित साइबर सुरक्षा लचीलेपन के साथ ''ओपन–सोर्स डेवलपमेट प्लेटफॉर्म'' पर स्वदेशी एड–टेक टूल को होस्ट करने की आवश्यकता है। यह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करेगा।

5.7 एनईपी प्रणाली में शिक्षकों के लाभ

एनईपी प्रणाली में शिक्षकों को मिलने वाले शीर्ष लाभ इस प्रकार हैं:

- एनईपी प्रणाली में समग्र शैक्षणिक विकास शिक्षकों के लिए भी लाभकारी होगा।
- हालांकि चुनौतीपूर्ण, शिक्षकों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का अवसर मिलेगा।
- शिक्षक आधुनिक युग में डिजिटल विभाजन को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
- शिक्षकों का शिक्षा प्रणाली के अन्य वर्गों, विशेषकर छात्रों के साथ संबंध बेहतर होगा।
- एनईपी प्रणाली भरोसेमंद है क्योंकि सरकार इसके लिए जवाबदेह है।
- शिक्षकों को देश के भविष्य में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और उसमें योगदान देने का मौका मिलेगा।
- संस्थानों के साथ मिलकर शिक्षक देश की शिक्षण प्रगति को बदलने में भूमिका निभा सकते हैं।

6. उपसंहार

हमारी हालिया शिक्षा नीति ने सिस्टम के भीतर विज्ञान, कला, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर, व्यावसायिक और शैक्षणिक आदि जैसे अंतरों को खत्म करने की दिशा में काम किया है। इसने एक अधिक छात्र–केंद्रित प्रणाली की भी कल्पना की है जो 21वीं सदी में आवश्यक वैचारिक समझ और कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। यह दूरदर्शी नीति मूल्यांकन पैटर्न (अधिक रचनात्मक के साथ) में बदलाव का भी सुझाव देती है। और ऑनलाइन शिक्षा पर इसका जोर ऑनलाइन स्कूली शिक्षा जैसे स्कूली शिक्षा के विकल्पों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। एनईपी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान की गई शिक्षण गुणवत्ता और उम्मीदवारों को पुरस्कार लौटाने के बीच संतुलन बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। शिक्षण पेशेवर इस तथ्य से खुश हो सकते हैं कि एनईपी 2020 के तहत सीखने का अनुभव एक सतत प्रक्रिया है और यहाँ रहने के लिए है। एनईपी शिक्षक प्रशिक्षण अनुभाग में आगे के अपडेट के लिए इस स्थान पर बने रहें।

7. सन्दर्भ

1. "एआईईईई". मानव संसाधन विकास मंत्रालय. मूल से 13 जुलाई 2012 को संग्रहीत. 15 जुलाई 2012 को पुनःप्राप्त.

2. चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020). "समझायाः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ना". द इंडियन एक्सप्रेस.
3. डी पी शर्मा "भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियाँ" पर. एडुवॉयस द्य शिक्षा उद्योग की आवाज़. 25 मई 2020.
4. अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (पीडीएफ) (रिपोर्ट). मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
5. जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020). "द हिंदू बताता है द्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्या प्रस्तावित किया है?" द हिंदू. आईएसएसएन 0971–751ग
6. मट्टू, अमिताभ (16 नवंबर 2019). "शिक्षा को सार्वजनिक वस्तु के रूप में मानना". द हिंदू. आईएसएसएन 0971–751ग. 21 नवंबर 2019 को पुनःप्राप्त।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.को संदर्भित।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः आपको जो कुछ भी जानना चाहिए". द टाइम्स ऑफ इंडिया.
9. एनसीईआरटी" (पीडीएफ). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 12 जुलाई 2009 को पुनःप्राप्त। (10). "राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र" (पीडीएफ). राष्ट्रीय
10. सूचना विज्ञान केंद्रः 38दृ45. मूल (पीडीएफ) से 31 जुलाई 2009 को संग्रहीत. 12 जुलाई2009 को पुनःप्राप्त।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र". पीडीएफ. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रः 38दृ45. 12 जुलाई 2009 को पुनःप्राप्त।
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986". राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। पृ. 38दृ45. मूल से 19 जून 2009 को संग्रहीत। 12 जुलाई 2009 को पुनःप्राप्त।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986". राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। पृ. 38दृ45. 12 जुलाई 2009 को पुनःप्राप्त। (मृत लिंक)
14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (जैसा कि 1992 में संशोधित किया गया)" (पीडीएफ)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मूल (पीडीएफ) से 26 नवंबर 2010 को संग्रहीत। 3 मार्च 2011 को पुनःप्राप्त।
15. नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातेंः मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीनतम समाचार, एमएचआरडी एनईपी आज समाचार अपडेट"। 29 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त।
16. नंदिनी, एड. (29 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें। स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे"। हिंदुस्तान टाइम्स।
17. "राज्य शिक्षा बोर्डो को राष्ट्रीय निकाय द्वारा विनियमित किया जाएगाः ड्राफ्ट एनईपी"। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 21 नवंबर 2019 को लिया गया।
18. शुक्ला, अमनदीप (29 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति 2020ः एनईपी शिक्षकों के लिए पेशेवर मानकों पर विचार करती है"। हिंदुस्तान टाइम्स।

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.